निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 09 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून** के माह 04/2012 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09/06/2017 से 15/06/2017 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. गुप्ता एवं श्री शशि कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 16/06/2012 से 19/06/2012 तक श्री ए.के. भारतीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सम्पूर्ण जिला उद्योग विकास क्षेत्र प्रोत्साहन का काम।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य (+) □	बचत (-) □	आधिक्य (+) □	बचत (-) □
2012-13			1429000	1423979	14378984	13894597				
2013-14			1406645	1406645	17277023	16680242				
2014-15			3740275	3740275	18727806	18074411				
2015-16			700000	700000	19750966	19441828				
2016-17			2103500	2103500	18792000	18465882				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
धनराशियां आवंटित एवं वितरित सिडकुल के द्वारा की जाती है।।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन **राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार** द्वारा किया जाता है। इकाई **C** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

.....

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा सम्पूर्ण जिला, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2012 एवं 08/2014 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **राज्य एवं केन्द्र द्वारा स्वीकृत एवं वितरित उपादानों से संबंधित प्रकरण** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम स्वीकृत एवं वितरित प्रकरणों के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर 1:- नियमानुसार वसूली की कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप `61.50 लाख न वसूला जाना ।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि मै0 एम0वी0 इंटरप्राइजेज़ जो कि रिक्लेम रबर निर्माण हेतु पंजीकृत किया गया था, फर्म ने 14-08-2007 से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था जिसके पश्चात फर्म को उद्योग विभाग द्वारा सिडकुल के माध्यम से रु० 30.00 लाख केंद्रीय पूंजी उपादान दिनांक 01-09-2009 को दिया गया था। दिनांक 22/04/2011 को फैक्टरी में आग लग गई थी अभिलेखानुसार अनुमानित नुकसान `24.93 करोड़ होना बताया हैं। केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान 2003 के शर्तानुसार केंद्रीय पूंजी उपादान दिये जाने के पश्चात इकाई को लगातार 5 वर्षो तक उत्पादनरत रहना अनिवार्य होगा, तथा एग्रीमंट डीड के शर्त 3(सी) के अनुसार Where the industrial unit of the Grantee goes out of production within five years from the date of commencement of production for short period not exceeding six months due to reasons beyond control such shortage of raw materials, power etc. लेकिन इकाई द्वारा दिनांक 14-08-2007 को उत्पादन प्रारम्भ कर दिनांक 22-04-2011 को अग्नि कांड के पश्चात उत्पादन नहीं किया जाना बताया है, अर्थात 4 वर्ष से पूर्व ही इकाई बंद हो गई थी। उल्लिखित शर्तानुसार इकाई को भुगतान की गई पूंजी उपादान की धनराशि ब्याज सहित वसूलनीय था, लेकिन कार्यालय महाप्रबंधक के पत्रांक 3431/के0पी0उपा0/मै0एम0बी0इन0पा0/2013-14 दिनांक 12 नवंबर, 2013 को अपर निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड को प्रेषित पत्र में बताया कि "उत्पादन की तिथि दिनांक 14-08-2007 से पाँच वर्ष पूर्ण कर चुकी है, यदि किसी इकाई में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन नहीं हो रहा है तो ऐसी इकाई के संबंध मे दी गई सहायता की वसूली की जानी न्यायसंगत नहीं है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उक्त इकाई से उपादान की वसूली हेतु इस स्तर से कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई है।" जबकि इकाई दिनांक 14-08-2007 से 22-04-2011 तक उत्पादनरत रही है, जो कि 04 वर्ष से कम है अर्थात कार्यालय द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को गलत सूचना प्रतिवेदित की गई । Agreement deed शर्त 3(ई) के अनुसार Where the guarantee in respect of the industrial unit fails to take reasonable, precautions for the safety of the Plant, Machinery, Tools, Appliances, Implements, Equipments etc. Procured partly or wholly with the help of the Capital Investment Subsidy against loss or damage from fire, accident or theft or fails to maintain the same in efficient working order. इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, देहरादून के प्रतिवेदनानुसार बीड कसिंग मशीन के वायर में शार्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लगना बताया है और अग्नि कांड में क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति `24.93 करोड़ पूर्णतः बीमित था, फिर भी इकाई को भुगतान की गई पूंजी उपादान की धनराशि `30.00 लाख मय ब्याज वसूली हेतु आतिथि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। न ही कार्यालय के द्वारा इकाई को बीमा कंपनी के द्वारा बीमित धनराशि प्राप्त हुई कि नही आतिथि तक मालूम नही किया गया है, न ही इकाई को पुनः चलाया गया। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "यथाशीघ्र वसूली की कार्यवाही कर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत की जायेगी"। विभाग की आख्या से स्पष्ट हैं कि विभाग के द्वारा उल्लिखित नियमानुसार वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी जबकि नियमानुसार इकाई को 05 वर्ष उत्पादनरत न रहने पर वसूली हेतु लिखा जाना चाहिए, तत्पश्चात इकाई की प्रत्युत्तरानुसार उल्लिखित नियम/शर्त की रोशनी में इकाई और उद्योग के हित में निर्णय लिया जाना चाहिए था। अर्थात दिनांक 14/08/2011 से मई, 2017 तक ` 30.00 लाख पर 18 प्रतिशत ब्याज आरोपित करते हुये( 30.00लाखx18%x5.83) कुल `61.50 लाख वसूला जाना हैं। अतः`61.50 लाख न वसूले जाने प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हें।

Hkkx nks ¼v½

izLrj 2- :0 69-39 yk[k dh nksuks bdkbZ;ksa ls dsUnzh; iwWath fuos"k miknku dh olwyh fd;k tkuk A

As per the para 11 of Central Capital Investment Subsidy scheme,2003 if the central Government/State government concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact, furnishing of false information the central government/state government may, after giving opportunity to the unit concerned of being heard, ask the unit to refund the grant or subsidy already received.

Further as para 14 after the receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progress Report to the State Government about its working for a period of 5 years after going into production.

As per Govt. of India guidelines/Instructions cash payment have not been considered. Plant&Machinery acquired after the registration and with-in one year from the date of commencement of commercial Production only has been considered. In bank finance cases fixed capital investment in plant& machinery as per bank appraisal has been considered as eligible for calculating CCISS. On the basis of the above, the amount of 15% subsidy to which you are entitled in determined at Rs. you are entitled in determined at Rs. 30.00 lakhs.

eSa0 Doklj ySCl izk0 fy0 [kljk u0 237 t vkS|ksfxd {ks= dqvkokyk nsgjknwu dh dsUnzh; iwWath fuos"k miknku nkok i=koyh dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk ?kksf'kr LFkk;h iwth fuos"k :0 1]06]50]048-00 ij 15 izfr"kr dh nj ls funs"kky; ds i=kad la[;k1858@DI(v)-CIS/2013-14 fnukad 30 जुलाई 2013 }kjk :0 15]97]507-00 dh Lohd`fr iznku dj nh x;hA

bZdkbZ }kjk tks lykaV ,oa e"khujh ij iwWth fuos"k :0 1]06]50]048-00 dk O;; o'kZ 2006&07 esa gksuk n"kkZ;k x;k FkkA bl lEcU/k esa okf.kT; dj foHkkx nsgjknwu ls lR;kiu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk

o’kZ 2006&07 esa QkeZ 16 ls dsoy :0 1]32]12]016-00 dh vk;frr vkS’kf/k;ksa dk dz; fd;k x;k gSA o’kZ 2006&07 ds vfUre dj fu/kkZj.k vkns”kkuqlkj lykaV ,oa e”khujh dk dz; fd;k gh ugh x;kA blfyए व्यापारी }kjk feF;k dFku izLrqr djds dsUnzh; iwWth fuos”k lgk;rk dk ykHk izkIr djk x;k Hkqxrku dh x;h /kujkf”k 15]97]507-00 ij 10 izfr”kr C;kt lfgr tek frfFk rd olwyh ;ksX; gSA

blh rjg bdkbZ eSllZ Xykscy eSfMdhV fy0 [kljk la[;k 323 ,e0vkbZ0lSUV`y gksi Vkmu dSEi jksM lsykdqbZ nsgjknwu dh dsUnzh; iwWath fuos”k miknku nkok ls lEcfU/kr i=koyh dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ ds }kjk tks o’kZ 2008&09 ,oa 2009&10 esa dz; lykaV ,oa e”khujh :0 2]87]88]491-00 dh ?kksf’kr dh x;h gSA ftl ij 15 izfr”kr :0 30-00 yk[k dk miknku No. 3553/D.I.(V)-CIS@2011-12 Dated 09 November 2011 ls izkIr fd;k x;k gSA bdkbZ dk okf.kT; dj dk;kZy; fodkl uxj ls lR;kiu djus ij ik;k x;k fd o’kZ 2008&09 esa vds{k.k fjiksVZ ys[kk vuqlkj :0 45]050-00 fnukad 31@03@2009@ dks dz; ?kksf’kr fd;k x;k FkkA ,oa o’kZ 2009&10 esa QkeZ 16 ls dsoy :0 85]88]120-00 ?kksf’kr dh x;h gSA vr% nksuksa o’kksZ esa dsoy :0 86]33]170-00 dh lykaV ,oa e”khusa bdkbZ }kjk dz; dh x;h FkhA vUrj :0 2]01]55]321-00 dk vf/kd dz; lykaV ,oa e”khujh esa fn[kkdj vf/kdre /kujkf”k :0 30-00 लाख dks izkIr fd;k x;k FkkA bdkbZ }kjk vius djksckj ds lEcU/k esa Hkh feF;k ?kks’k.kk fd x;h Fkh tSlkfd bZdkbZ }kjk okf.kT; dj dk;kZy; fodkl uxj esa viuk jftLVs”ku fnukad 12@07@2007 dks eSllZ vklqek esMhdy fy0 b.MLVh;y ,fj;k lsykdqbZ ds uke ls djk;k x;k FkkA ftldk fVu la[;k 05007322652 gSA dEiuh ds vfHkys[kksa ds vuqlkj fnukad 01@09@2010 ls QeZ dk uke cnydj eSllZ Xykscy eSfMdhV fy0 ij dsUnzh; iwWath fuos”k miknku lgk;rk izkIr dh x;h gSA bdkbZ }kjk egkizcU/kd dk;kZy; esa vius izFke mRiknu dh frfFk 18@04@2009 ?kksf’kr dh x;h FkhA tksfd iw.kZrk% xyr FkhA D;ksfd bdkbZ }kjk izR;ds ekg vius dkjksckj ls lEcfU/kr fodz; fooj.kh esa ekg twu 2009 dk dz; fodz; “kwU; n”kkZ;k x;k gSa] bdkbZ }kjk feF;k ?kks’k.kk djds dsUnzh; iwWath fuos”k lgk;rk dk ykHk izkIr fd;k x;k gSA blfy;s Hkqxrku dh x;h /kujkf”k :0 30-00 yk[k 10 izfr”kr C;kt lfgr tek frfFk rd olwyh ;ksX; gSA

bl lEcU/k esa foHkkx ls iwNus ij crk;k x;k fd rF;ks ,oa vkWadMksa dh iqf'V dh tkrh gsS]pkgs x;s vfHkys[kks dks bdkbZ ls izkIr dj miyC/k djk fn;k tk;sxkA

foHkkx mRrj ekU; ugh gSa]D;ksfd dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk 2003 esa tkjh vf/klwpuk ,oa le; le; ij tkjh "kklukns"kks esa Li'V dgk x;k Fkk fd ;fn bdkbZ }kjk feF;k ?kks'k.kk djds miknku dk ykHk izkIr fd;k tkrk gS]rks bdkbZ ls mDr /kujkf"k dh olwyh Hkkjr ljdkj ds i=kad la[;k 3(7)/2013-SPS dated 13th September ,2013 esa izko|kfur C;kt 10 izfr"kr ls x.kuk djds fu/kkZfjr ys[kk"kh'kZ esa tek dh tk;sA bdkbZ }kjk fujUrj feF;k dFku izLrqr dj ;g ykHk izkIr fd;k x;k FkkA ftldh olwyh :0 30-00 yk[k 10 izfr"kr C;kt lfgr tek frfFk rd olwyuh; gSA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

Hkkx nks ¼ब½

izLrj 1:- :0 53-75 yk[k dh bdkbZ dks Lis"ky iSdst 2013 ds vUrxZr dsUnzh; iwWth fuos"k miknku dk vfu;fer nkok Lohd`r fd;k tkukA

Vide No. 3(2)/2008-SPS Government of India Ministry of Commerce &Industry Department of Industrial Policy & Promotion (Special Package Section) Udyog Bhawan,New Delhi Dated the,25th January 2011 clarifies that units located in the same khasra number/location/Industrial area would be eligible for the subsidy if they are separate and distinct and registered as such under the relevant State/Central Laws. esa ;g er Li'V djk x;k fd ;fn nks vkS|ksfxd bdkbZ ,d gh [kljk uEcj esa vyx vyx ,d gh djksckj djus ds fy, LFkkfir dh x;h g]S vFkkZr nksuks bdkbZ;kWa dk fof/kd vfLrRo vyx gksa] vkSj og dsUn@ljdkj ds dk;kZy; esa vius dkjksckj dks djus ds fy, vyx&vyx iathd`r djk;h x;h gksa rks mu bdkbZ;kWa dks Hkh dsUnzh; iWwth fuos"k miknku ;kstuk ykHk fn;k tk ldrkA ijUrq izFke bdkbZ dh ?kksf'kr ckUpzksa dks ;g ykHk vuqeU; gh ugh gS] D;ksfd ;kstuk esa Li'V dgk x;k Fkk fd o'kZ 2003 ls iwoZ LFkkfir gks pqdh bdkbZ;ksa dks ftuds }kjk ;kstuk izkjEHk djus ds fnukad ds ckn ls 25 izfr"kr foLrkjhdj.k fd;k x;k gks] ,oa og bdkbZ ftuds }kjk ;kstuk izkjEHk gksus dh vof/k ls lHkh O;olkf;d vkSipkfjdrk,s Hkkjr ljdkj@jkT; ljdkj ds mYyf[kr fu;eksa vuqlkj iw.kZ dh x;h gks] ogh bdkbZ;kWa ik= gks ldrh gSA

dk;kZy; dh ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;k x;k fd bdkbZ eSllZ vkse izdk"k ,.M laUl½Na-6-Panditwari dehradun. ftldk fVu la[;k 05012123085 gSA bdkbZ }kjk ?kksf'kr ckUp eSllZ fn iy xkz.M ¼, ;wfuV vkQ vkse izdk"k ,.M laUl½lgkjuiqj jksM U;w lCth e.Mh fujtuiqj nsgjknwu dks Lis"ky iSdst 2013 ds vUrxZr dsUnzh; iwWath fuos"k :0 3]91]52]902-00 ij 15 izfr"kr vuqnku :0 50-00 yk[k funs"kky; ds i=kad la[;k 260/D.I.(V)-CCISS-2013/2016-17 Dated 18th October 2016 }kjk Lohd`r dh x;h gSA bdkbZ ds }kjk ftl Hkwwfe ij O;olkf;d xrfof/k;kWa n"kkrs gq,s :0 50-00 yk[k dk ykHk izkIr fd;k x;k gSA og Hkwfe O;olkf;d iz;kstu ls brj vkoklh; iz;kstu gsrq dz; dh x;h FkhA rFkk ftldk ekufp= vkns"k i= la0 lh003011011 fnukad 15@12@2010 }kjk uxj fu;kstd ,e0Mh0Mh0, }kjk vkoklh; fuekZ.k gsrq Lohd`r fd;k x;k FkkA bdkbZ }kjk vkns"kks dh vogsyuk djrs gq, vkolh; iz;kstu djus ds ctk, O;olkf;d fuekZ.k fd;k x;k rFkk elwjh nsgjknwu fodkl izkf|dj.k lh 322 fnukad 5@11@2012 esa deikmfMx djk fy;k x;kA bdkbZ }kjk vius O;olkf;d dkjksckj dh lwpuk okf.kT; dj foHkkx nsgjknwu esa eSllZ vkse izdk"k ,.M laUl Na-6-Panditwari dehradun. ds uke lss izLrqr dh tk jgh gSA bdkbZ }kjk gksVy ,oa jsLVksjsUV dk mRiknu fnukad 13@04@2014 ls crk;k x;k gS] tcfd [kkn~; foHkkx }kjk iathdj.k izek.k&i= la[;k 22614030001441 fnukad

18@06@2014 dks vkoafVr dh x;h FkhA bdkbZ ds }kjk ljk; ,DV ;k i;ZVu foHkkx esa iathdj.k lEcfU/kr vfHkys[k Hkh izLrqr ugh fd;s x;s FksA bdkbZ }kjk

Agreement Deed esa QeZ eSllZ vkse izdk”k ,.M laUl dk uke cnydj Jh vkse izdk”k ,.M laUl dj fn;k] tcfd mRiknu dh frfFk ls ikWap o’kksa rd bdkbZ ds uke esa ifjorZu ugh fd;k tk ldrk gSA mijksDr rF;ksa ls Li’V gS] fd bdkbZ }kjk feF;k rF; izLrqr djds dsUnzh; iwWath fuos”k miknku ;kstuk dk ykHk ysus gsrq nkok izLrqr fd;k x;k FkkA blfy;sa bdkbZ dks Hkqxrku dh x;h /kujkf”k :0 50-00 yk[k e; 10 izfr”kr C;kt lfgr tek frfFk rd olwyuh; gSA

bl lEcU/k esa foHkkx ls iwNus ij crk;k x;k fd rF;ksa ,oa vkWdMksa dh iqf’V dh tkrh gS]fu;ekuqlkj dk;Zokgh dh tk;sxhA

foHkkxh; mRrj ekU; ugh gS] D;ksfd dk;kZy; }kjk izLrqr vfHky[kksa dh leqfpr tkWap djus ds fy;s m|ksx funs”kky; mRrjk[k.M ds i=kad la[;k 3270@m0fu0¼11½@fo-,-vkS-izks-uh-@ek-n”kZu@2014&15 fnukad 10@11@2014 esa Li’V dgk x;k fd miknku ds lEcU/k esa le; le; ij tkjh funs”ksZ dk dBksjrk ls ikyu djs vkSj okLrfod ewY; dk lR;kiu djus ds ckn gh laLrqfr dh dk;Zokgh djsaA funs”kky; dks nkok Hkstrs le; ;g /;ku j[k tk; fd okLrfod ewY; dk lR;kiu dj fy;k x;k gS vksj bldh iqf’V esa vko”;d dkxtkr layXu dj fn;s x;s gSA blds vfrfjDr bl lEcU/k esa nkosnkj dk lR;kfir “kiFk&i= Hkh izLrqr fd;k tk;A ijUrq foHkkx }kjk nkok i=koyh dh leqfpr tkWap fd;s fcuk gh nkok izdj.k dks laLrqr dj funs”kky; dks nkok /kujkf”k Lohd`r djus ds fy;s izsf’kr dj fn;k x;kA funs”kky; Lrj ij Hkh nkok izdj.k dh leqfpr tkWap fd;s fcuk gh lfefr ds le{k izLrqr dj nkos ij Lohd`fr izkIr dj yh x;h tksfd dsUnzh; iwwWath fuos”k miknku fu;ekoyh ,oa le; le; ij tkjh fu;eksa ds fo:} FkkA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2:- रु0 171.78 लाख का केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान के सापेक्ष अनियमित स्वीकृति/वितरण ।

As per the Government of India Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy&Promotion) Notification New Delhi,the 4th February 2014 bearing F.No.2(1)/2013-SPS, The Central Investment Subsidy Scheme 2013 provides in Para No. 6 that the industrial unit registered before 07-01-2013 under the erstwhile scheme of subsidies and have filed the claims within one year from the date of commencement of commercial production/operation would be eligible for subsidies under erstwhile scheme. Units which have registered on or after 07-01-2013 would be covered under the present scheme.

Further,The Government is pleased to notify the extension of the following scheme of Central Grant or Subsidy under Special Package –II for Industrial units in the states Uttarakhand with a view to accelerating the industrial development in these States.

As per the Para -4 of the notification All new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion, would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of investment of Plant & Machinery, subject to a ceiling of Rs- 30 lakhs, Micro, Small and Medium enterprises would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of the investment in plant & machinery subject to a ceiling of Rs. 50 lakh.

As per the Para- 11 of the notification A unit can avail subsidy only under a single scheme, either from the central Government or from the state Government. A unit seeking subsidy should certify that it has not obtained or applied for subsidy for the same purpose or activity from any other Ministry or Department of the Government of India or State Government.

Vide No. 3(2)/2008-SPS Government of India Ministry of Commerce &Industry Department of Industrial Policy & Promotion (Special Package Section) Udyog Bhawan,New Delhi Dated the,25th January 2011 clarifies that units located in the same khasra number/location/Industrial area would be eligible for the subsidy if they are separate and distinct and registered as such under the relevant State/Central Laws.

dsUnzh; iwWath fuos"k miknku ;kstukUrxZr fnukad 07@01@2013 foLrkjhdj.k ds iwoZ dqy 05 bdkbZ;k iathd`r Fkh** जिनको dqy :0 14363403.00 **dk miknku forj.k fd;k x;k Fkk mUgh 05 bdkbZ;ksa dks fnukad 07@01@2013 ds ckn foLrkjhdj.k ij :0** 17177614-00 **Lohd`r fd;s x;sA mDr bdkbZ;ksa dk fooj.k layXu gS tksfd mYyf[kr izLrj la[;k 6 ds fo:} FkhA D;ksfd mDr bdkbZ;kWa fnukad 07@01@2013 ds iwoZ dsUnzh; iwWath fuos"k miknku ;kstuk 2003 ds vUrxZr iathd`r FkhA

आगे उल्लिखित प्रस्तर 11 के अनुसार भी जब किसी इकाई को एक बार राज्य या केंद्र द्वारा उपादान दी जाती है, तो पुनः किसी भी योजनांतर्गत दुबारा उपादान का लाभ नहीं दिया जाना है, इसके विपरीत जिला उद्योग केंद्र, देहरादून द्वारा संस्तुत तथा निदेशालय/राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत कर 05 इकाइयो को दो-दो बार

उपादान स्वीकृत/वितरित की गई, जो कि उल्लिखित नियमो के विरुद्ध है । इसे इंगित करने पर विभागीय उत्तर में बताया कि "प्रकरण संज्ञान में लिया जाएगा" ।

इस प्रकार योजना के शर्तो के विपरीत पुनः उन्ही इकाइयो को दुबारा केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान रु0 171.78 लाख स्वीकृत किया गया है, जिन्हें पूर्व में ही उपादान का लाभ दिया गया था ।

अतः रु0 171.78 लाख अनियमित स्वीकृत किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 3:- रु0 24.12 लाख केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान का अनियमित भुगतान ।

As per central capital investment scheme, 2003 notification, it is provided in paras :-

5(b). 'New Industrial Unit' means an industrial unit for the setting of which effective steps were not taken prior to 7th January, 2003.

6. All eligible industrial units located in the Growth Centres or HOE or industrial estates/parks/export promotion zones and commercial estates set up in Uttaranchal and Himachal Pradesh shall be given capital investment subsidy at the rate of 15% of their fixed capital investment in respect of new units or additional investment in respect of substantial expansion by an existing units in the plant and machinery, subject to a maximum ceiling of Rs. 30 lakh.

9. Industrial unit eligible for subsidy under the scheme will get themselves registered with the State Industries Department prior to taking effective steps for setting up the new units and indicate, in their claim for investment subsidy, their assessment of the total fixed capital to be invested by them in the plant and machinery of their unit.

10.1 In respect of a new industrial unit set up without assistance from the financial institutions or the State Government, the subsidy will be disbursed to the unit by designated Agency on the recommendation of the State Government at the time the unit goes into production.

कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि मै0 एन0टी0एल0 इण्डिया लि0 यूनिट-1 भूखंड सं0 ई-25 यू॰पी॰एस॰आइ॰डी॰सी॰ औद्योगिक क्षेत्र सेलकुई देहरादून को केन्द्रीय पूंजी उपादान वर्ष 2015-16 में रु0 2412099.00 वितरित किया गया। उक्त इकाई को नई इकाई के वर्ग में उपरोक्त उपादान स्वीकृत किया गया था।

ई0एम0 पार्ट-I के अनुसार इकाई का पंजीकरण तिथि 09-04-2008 है तथा ई0एम0 पार्ट-II के अनुसार इकाई की उत्पादन तिथि 18-06-2008 है। उक्त दोनों तिथियो के बीच इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के सापेक्ष विभाग द्वारा अनुमोदित बिल की कुल धनराशि रु0 1333595.00 का व्यय के रूप में दर्शाया गया है। जबकि उद्योग विभाग द्वारा इकाई के उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि 18-06-2008 से एक वर्ष के भीतर अर्थात 17-09-2006 तक इकाई द्वारा किए गए पूंजी निवेश रु0 16080663 के आधार पर पूंजी निवेश उपादान की गणना की गई, जो कि पूंजी निवेश नियमो के विपरीत है वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि तक किए गए पूंजी पर किए गए व्यय ही पूंजी निवेश है उसके बाद किए गए पूंजी निवेश संयंत्र तथा मशीनरी में विस्तार के संबंध में अतिरिक्त निवेश है। जबकि केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान नई ओद्योगिक इकाइयो के संबंध में किए गए निवेश अथवा संयंत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त विस्तार के संबंध में अतिरिक्त निवेश पर दिया जाएगा, न की दोनों पर ।

उक्त इकाई कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 22-08-2007 को मै0 NTL private Ltd॰ जिसका कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 06-04-2002 को निगमित था, का नाम परिवर्तित कर निगमित किया गया अर्थात उक्त इकाई को नई इकाई के वर्ग में केंद्रीय पूंजी उपादान दिया गया जबकि उक्त इकाई दिनांक 7 जनवरी, 2003 से पूर्व में कार्यरत थी, दिनांक 22-08-2007 को मात्र नाम परिवर्तित किया गया था। अतः इकाई को नई इकाई के वर्ग मे केंद्रीय पूंजी उपादान सहायता हेतु पात्रता नहीं थी ।

इकाई द्वारा उत्पादन तिथि तक प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए निवेश के सापेक्ष 15% की दर से उपादान दिया जा सकता था, न की उत्पादन तिथि के पश्चात इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए खर्च पर ।

विभागीय उत्तर मे बताया कि " प्रकरण संज्ञान में लेते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। "

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Hkkx nks c

izLrj 4:- :0 22-46 yk[k dh fo”ks’k jkT; iwWath fuos”k lgk;rk dh olwyh 18 izfr”kr C;kt lfgr fd;k tkukA

fo”ks’k ,dhd`r vkS|ksfxr izksRlkgu uhfr 2008 ;Fkk la”kksf/kr 2011 ds vUrxZr vf/klwpuk la0 488@vkS0fo0@VII-II-08@2008 fnukad 29@09@2008 }kjk fo”ks’k jkT; iwWath fuos”k miknku ds vUrxZr bdkb;kW eSllZ “kqHke VwfjLV gksVy [kljk u0&1520 xzke &iqjksMh pdjkrk]elwjh jksM]dkylh nsgjknwu dks bdkbZ esa vf/k’Bkfir lykaV ,oa e”khujh en esa :0 43]54]944-00 dk iwWath fuos”k izekf.kr djrs gq,s 25 izfr”kr dh nj ls :0 10]88]736-00 dk miknku Hkqxrku fd;k x;k FkkA rFkk eS0 ds”kj gksVy ,.M jsLVksjsUV ekxVh iks[kjh dkylh pdjkrk nsgjknwu dks Hkh dqy iwWath fuos”k /kujkf”k :0 4631090.00 dk 25 izfr”kr :0 1157772.00 fo”ks’k jkT; iwWath fuos”k Hkqxrku dh x;h FkhA bl lEcU/k esa nksuks bdkbZ }kjk fcfYMx fuekZ.k esa n”kkZ;h x;h O;; /kujkf”k ds fcy@okmpjksa dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk tks gksVy fuekZ.k esa O;; /kujkf”k ds fcy@okmpj izLrqr fd;s Fksa] og fcy@okmpj fu/kkZfjr izk:i esa ugh Fkas] ftl ysVj iSM ij fcy cukdj izLrqr fd;s x;s gS ml ij i=kpkj dk irk] fVu la[;k Hkh mfYyf[kr ugh Fkh] rFkk bdkbZ }kjk O;; n”kkZ;h x;h /kujkf”k dk Hkqxrku Hkh lfonkdkj ,o adz; dh x;h lykaV ,oa e”khujh dh QeksaZ dks udn gksuk n”kkZ;k x;k Fkk]tksfd fo”ks’k jkT; iwWth ;kstuk dk Li’V mYy?ku FkkA bdkbZ }kjk vius@QeZ ds cSd ,dkmUV LVsVesUV dh Nk;kizfr;kWa Hkh izLrqr ugh dh x;h Fkh]ftlls ;g izekf.kr gks lds fd Hkqxrku dh frfFk;ksa esa muds [kkrksa esa Hkqxrku dh x;h /kujkf”k miyC/k Hkh Fkh] ftldk udn vkgj.k fd;k x;k gksA fo”ks’k ,dhd`r vkS|ksfxr izksRlkgu uhfr 2008 ;Fkk la”kksf/kr&2011 ds izko|kuks ds vUrxZr udn Hkqxrku fd x;h /kujkf”k dks nkok x.kuk esa “kkfey ugh fd;k tkrk gSA mijksDr rF;ksa ls Li’V Fkk]fd foHkkx ds }kjk fu;eksa dk ikyu lqfuf”pr fd;s fcuk gh bdkbZ dks vuSfrd ykHk igqpkus ds m}s”; ls nkok /kujkf”k dks Lohd`r dj bdkbZ;ksa dks Hkqxrku fd;k x;k FkkA tcfd vk;dj vf/kfu;e ds izko|kuksa vuqlkj :0 20]000 ls vf/kd fd;s tkus okys fdlh Hkh Hkqxrku dks pSd@cSd M`kQV@vkj0Vh0th0,l0 ls fd;k tkuk pkfg,s FkkA blfy;s mYyf[kr nksuks bdkbZ;ksa dks Hkqxrku dh x;h /kujkf”k dh olwyh 18 izfr”kr C;kt lfgr tek frfFk rd olwyuh; gSA

bl lEcU/k esa foHkkx ls iwNus ij crk;k x;k fd lEizs{kk ny dh vkifRr mfpr gS] Hkfo’; gsrq uksV fd;kA

foHkkxh; mRrj ekU; ugh gSa]D;ksfd tc fu;eksa esa Li’V izko|ku Fkk] fd nkok dh x.kuk esa udn Hkqxrku dh /kujkf”k;ksa dks lEefyr gh ugh fd;k tk;sxkA rks fo”ks’k jkT; iwWath miknku ls lEcfU/kr fu;eksa dk ikyu lqfuf”pr djrs gq,s bdkbZ dk nkok fujLr D;ks ugh fd;k x;k Fkk]bdkbZ ds nkok dks laLrqr dj funs”kky; dks Lohd`fr djus ds fy;s izsf’kr djuk rFkk funs”kky; Lrj ij tkjh vkns”kks dk vuqJo.k fd;s fcuk gh nkok Lohd`r dj bdkbZ;ksa dks Hkqxrku fd;k tkuk Hkh fu/kkZfjr izko|kuksa vuqlkj vuqfpr FkkA blfy;s bdkbZ;ksa dks Hkqxrku dh x;h /kujkf”k;kWa 18 izfr”kr C;kt lfgr tek frfFk rd olwyuh; gSA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

Hkkx nks¼ c½

izLrj 5:- :0 30-00 yk[k dk izFke bdkbZ dh ?kksf'kr ckUp dks vfu;fer miknku Lohd`r fd;k tkukA

Vide No. 3(2)/2008-SPS Government of India Ministry of Commerce &Industry Department of Industrial Policy & Promotion (Special Package Section) Udyog Bhawan,New Delhi Dated the,25th January 2011 clarifies that units located in the same khasra number/location/Industrial area would be eligible for the subsidy if they are separate and distinct and registered as such under the relevant State/Central Laws. esa ;g er Li'V djk x;k fd ;fn nks vkS|ksfxd bdkbZ ,d gh [kljk uEcj esa vyx vyx ,d gh djksckj djus ds fy, LFkkfir dh x;h g]S vFkkZr nksuks bdkbZ;kWa dk fof/kd vfLrRo vyx gksa] vkSj og dsUn@ljdkj ds dk;kZy; esa vius dkjksckj dks djus ds fy, vyx&vyx iathd`r djk;h x;h gksa rks mu bdkbZ;kWa dks Hkh dsUnzh; iWwth fuos"k miknku ;kstuk ykHk fn;k tk ldrk gSA

dk;kZy; dh ys[kkijh{kk ds nkSjku m/s Zircon Technologies Limited (unit -2) Khasra Ni0 1017,1019,1021, Camp Road Selaqui Dehradun dh dsUnzh; iwWath nkok i=koyh dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd bldh izFke bdkbZ dks iwoZ esa gh dsUnzh; iwWath fuos"k miknku lgk;rk ykHk vuqeU; fd;k tk pqdk FkkA rRi"pkr bdkbZ ds }kjk foLrkjhdj.k esa fd;s x;s-lykaV ,oa e"khujh ij iwWth fuos"k :0 6]91]19]700-00 ds O;; ij :0 30-00 yk[k nkok bdkbZ ds }kjk izLrqr fd;k x;k FkkA dk;kZy; ds vf/kdkfj;ksa }kjk mDr nkok O;; vfHky[kksa esa n"kkZ;h lykaV ,oa e"khujh rFkk Hkqxrku /kujkf"k vfHkys[kksa ¼QkeZ 16,chtd]fMyhojh pkyku½ dk lR;kiu okf.kT; dj foHkkx fodkluxj esa bdkbZ ds }kjk ?kksf'kr vfHkys[kksa ls djk;s fcuk gh मात्र इकाई द्वारा घोषित प्रमाण पत्र का ही laLrqr dj Lohd`fr djus gsrq funs"kky; esa izsf'kr dj fn;k x;k] funs"kky; }kjk Hkh vlR;kfir vfHkys[kksa ij fcuk vkifRr yxk;s gh i=kad la[;k 2591/D.I.(V)-CCISS-2013/2016-17 dated 18 october 2016 Hkh :0 30-00 yk[k dh Lohd`fr iznku dj nh x;h tksfd Hkkjr ljdkj }kjk tkjh vkS|ksfxd uhfr 2003 ds izko|kuksa dk Li'V mYy?kau gSaA क्योंकि मूल बीजक एवं फॉर्म 16 के बिना दावा धनराशि संस्तुत एवं स्वीकृत करना अनियमित था।

bl संबंध esa foHkkx ls iwNus ij crk;k x;k fd rF;ksa ,oa vkWdMksa dh iqf'V dh tkrh gS] rFkk Hkkjr ljdkj }kjk o'kZ 2003 esa tkjh vf/klwpuk esa ;g dgh Hkh ugh dgk x;k gS fd izFke bdkbZ dh ckzUp dks Hkh dsUnzh; iwWath fuos"k miknku ;kstuk dk ykHk vuqeU; fd;k tk;sxkA

foHkkxh; mRrj esa Lohdkj fd;k x;k gS]fd Hkkjr ljdkj }kjk tkjh o'kZ 2003 dh vf/klwpuk esa ;g dgh Hkh ugh dgk x;k Fkk fd bdkbZ dh ?kksf'kr ckzUpksa dks Hkh ;g ykHk vuqeU; fd;k tk;sxkA izFke bdkbZ ds okf.kT; iath;u esa

?kksf'kr dh x;h ckzUp ftlds }kjk izFke bdkbZ dk tkWao odZ dk;Z gh fd;k tkrk gS] blfy;as ml bdkbZ dh ckUp

}kjk vyx ls dksbZ Hkh dz; fodz; leO;ogkj dsUnz@jkT; ljdkj ds dk;kZy; esa ?kksf'kr ugh fd;k tkrk gSA bl lecU/k esa dk;kZy; vk;qDr dj ds i=kad la[;k 322@2011&12 nsgjknwu }kjk oSV vf/kfu;e 2005 dh /kkjk &57 ds vUrxZr fnukad 28 vizsy 2011 dks loZ Jh ,dj bySDV`hdy izk0fy0]IykaV ua0 1,&1ch lsDVj 8B-IIE flMdqy gfj}kj ds ikfjr fu.kZ; esa dgk x;k gSA fd ;wfuV&1 esa vfrfjDr rhu vU; ;wfuV vFkkZr ;wfuV 2]3]4 Hkh cgknjkckn esa fLFkr gS tks O;kikjh dh job work/ancillary ds :i esa dk;Zjr gSA lHkh ;wfuVsa mudh lEiw.kZ bdkbZ dk fgLlk gSa vr% mUgsa vyx ls ykHk ugh feysxkA blfy;sa bdkbZ dh ;wfuV&2 dks Hkh vyx ls dsUnzh; iWwth fuos"k miknku ;kstuk dk ykHk vuqeU; ugh fd;k tk ldrk gSA
vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

भाग दो (ब)

प्रस्तर 6:- नियमानुसार वसूली की कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप ` 343.73 लाख की वसूली न किया जाना ।

कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पूर्व मे वितरित ऋण से संबन्धित पत्रावलियो की जांच मे पाया कि एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना मे Rs 249.02 लाख, जिला उद्योग केंद्र मार्जिन मनी ऋण योजना मे Rs 70.19 लाख, जिला उद्योग केंद्र ऋण योजना मे Rs 9.55 लाख एवं विकास केंद्र ऋण योजना मे Rs 14.57 लाख अर्थात उक्तलिखित 4 योजनाओ मे दिये गए ऋण मद मे आतिथि तक (ब्याज सहित) Rs 343.73 लाख की वसूली किया जाना अवशेष है| उक्तलिखित धनराशि में से मात्र Rs 44.59 लाख की आर॰सी॰ जारी की गई है एवं धनराशि Rs 299.14 लाख की आतिथि तक आर॰सी॰ जारी नहीं की गई है। (विवरण संलग्न) यदि विभाग के द्वारा यथासमय/यथा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाती तो धनराशियाँ वसूल ली जाती, अर्थात विभाग की उदासीनता के कारण प्रश्नगत धनराशियाँ आथिति तक वसूल नही की जा सकी| इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि, "अब उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष शीघ्र ही वसूली हेतु आर0सी0 जारी करवाने की कार्यवाही की जाएगी। " इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा वसूली नियमावली के अनुसार वसूली की कार्यवाही नहीं की गई है अतः नियमानुसार वसूली की कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप `343.73 लाख की वसूली न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 7 : – रु0 223.75 लाख स्वीकृत उपादान का 3/2 वर्षो के पश्चात वितरण न किया जाना ।

As per the Central Capital Investment Subsidy Scheme,2013 notification,The Directorate of Industries (DI) should ensure that all claims are placed before the State Level Committee(SLC) within 150 days from the date of receipt of the claims. In exceptional circumstances,if there is delay,then the reason for the same must be provided in writing by the concerned authorities of DI.

And Meeting of SLC must be held at least once in a quarter to avoid accumulation of cases pertaining to claims under the schemes.

dsUnzh; iwWath fuos"k miknku ;kstukUrxZr 18 bdkbZ;ksa ¼lwph संलग्न½ dks dqy :0 22375296.00 miknku /kujkf"k Lohd`r dh x;h] इनमे से एक भी इकाई को 3/2 o'kksZ ds i"pkr Hkh /kujkf"k dks forjhr ugh fd;k x;k FkkA

उल्लिखित नियमानुसार उपादान दावे की तिथि से 150 दिन के अंदर राज्य स्तरीय समिति के सामने रखा जाना चाहिए एवं समिति की कम से कम एक सभा त्रैमासिक में की जानी चाहिए । इसे संज्ञान में लाये जाने पर विभागीय उत्तर में बताया कि "प्रकरण संज्ञान में लिया जाएगा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । "

इस प्रकार उपादान स्वीकृत करने के पश्चात इकाइयो को धनराशियों का वितरण ही नहीं किया गया है, जिससे उद्योग को प्रोत्साहन के स्थान पर पर हतोत्साहित किया जा रहा है।

अतः रु0 223.75 लाख स्वीकृत उपादान 3/2 वर्षो के पश्चात भी वितरित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 1:- ` 9.97 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू गठित न किया जाना ।

कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि जिला उद्योग केंद्र के द्वारा एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजनांतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र (सहसपुर) का वृहद निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु रु0 9.97 लाख का आगणन अधिशासी अभियंता सिचाँई परिकल्प मंडल, रुड़की द्वारा प्रस्तुत किया गया था, के सापेक्ष दिनांक 02-07-2016 को रु0 747750.00 (75%) अवमुक्त किया गया था। तत्पश्चात रु0 239480.00 दिनांक 21-02-2017 को अवमुक्त की गई थी। इस संबंध में महाप्रबंधक द्वारा सिंचाई विभाग के साथ अनुबंध (एमओयू) किए जाने का निर्देश दिया था लेकिन पत्रावली की जांच मे अनुबंध या एमओयू किया गया हो, साक्ष्य उपलब्ध नहीं था । जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कार्य कब आरंभ कर कब पूर्ण किया जाना था तथा कार्यदायी संस्था द्वारा इस कार्यालय को अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष अनुबंध की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि का अनुबंध गठित कर कार्य करवाया जा रहा है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि, "भविष्य में सभी निर्माण कार्यार्थ एमओयू की जाएगी ।" इससे स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू गठित नहीं किया गया है, जिससे निर्माण कार्यार्थ अवमुक्त की गई धनराशियों के सापेक्ष प्राक्कलनानुसार व्यय की गई है या नहीं, सुनिश्चित नहीं होता अतः ` 9.97 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू गठित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
14/2012-13	शून्य	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
14/2012-13	भाग-II 'अ' प्रस्तर- शून्य भाग-II 'ब' प्रस्तर-01,02		विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है अतः प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती कौशल्या बंधु	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र
(ii)	श्री डी.सी. जुयाल	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र
(iii)	श्री राजेन्द्र कुमार	प्रभारी जिला उद्योग केन्द्र
(iv)	श्री शिखर सक्सैना	महाप्रबंधक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2